

किसी प्रकार की खानापूर्ति व उदासीनता पाई तो संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जावेगी-जिला कलक्टर

**जिला कलक्टर ने ली केंद्र व
राज्य सरकार की योजनाओं व
बजट घोषणाओं आदि की
समीक्षा बैठक**

जयपुर टाइम्स

अलवर(निस.)। जिला कलकटर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं, बजट घोषणाओं, राजस्थान संपर्क पोर्टल, अंतर विभागीय लिंगित कार्यों आदि की विस्तृत समीक्षा कर जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिला कलकटर ने जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिले में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को उनकी मंशा के अनुरूप धारातल पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित कराये। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को इन योजनाओं से जोड़कर उन्हें लाभावित कराया जावे। रेंडम आधार पर इन योजनाओं की जांच की जाएगी। यदि इनके संचालन में किसी प्रकार की



खानापूर्ति व उदासीनता पाई गई तो संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जावेगी। उन्होंने राजस्थान स पर्क पोर्टल की समीक्षा कर निर्देश दिये कि प्रतिदिन संबंधित अधिकारी पोर्टल का अवलोकन कर इस पर आने वाली परिवेदनाओं का गुणवत्ता के साथ निस्तारण

करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने निर्वेश दिये कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जनसुनवाई आदि से प्राप्त परिवेदनाओं का भी गुणवत्ता के साथ त्वरित निराकरण किया जावे। पोर्टल का अवलोकन नहीं करने, परिवेदनाओं के निस्तारण में उदासीनता बरतने व निस्तारण का कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं

करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जावेगी। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक से संबंधित परिवेदनाएं अधिक समय तक लंबित रखने पर नाराजगी जाहिर कर तुरंत दोनों प्रकरणों का निस्तारण कराने के निर्देश दिये। जिला कलक्टर ने जिले के लिए हुई बजट घोषणाओं की

समीक्षा कर निर्देश दिये तब निधारत टाइम लाइन के अनुरूप कार्यों को चरणबद्ध रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। राज्य स्तर से संबंधित बिंदुओं को समय पर अवगत कराए ताकि उनका समयबद्ध रूप से निराकरण कराया जा सके। साथ ही उन्होंने निर्देश दिये कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जावे। कार्यों की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने गुरु गोवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के तहत जिले के रामगढ़ ब्लॉक का चयन होने की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के 41 ब्लॉक में से अलवर जिले के रामगढ़ ब्लॉक का चयन किया गया है। इस योजना के तहत पिछडे ब्लॉक में सामाजिक एवं आर्थिक विकास कार्य किए जाएंगे। इसके लिए डेढ़ करोड़ रुपये का विशेष बजट आवंटित हुआ है। उन्होंने योजना के रामगढ़ में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को स्वयं मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये। इसके पश्चात जिला कलक्टर ने प्रोजेक्ट समृद्ध किसान के साथ कृषि व किसानों से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों

का निदंश दिय थक आपसा समयन्य रखकर किसानों को न केवल योजनाओं से जोड़े बल्कि उनका लाभ दिलाकर उन्हें समृद्धि की ओर लाने की दिशा में कार्य करें। बैठक में एडीएम प्रथम मुकेश कायथवाल, यूआईटी सचिव धीगढ़े स्नेहल नाना, डीएफओ अलवर राजेन्द्र हुड़ा, डीटीओ सुरेश यादव, सरस डेयरी की एमडी सुनीता यादव, सीएमएचआर डॉ. योगेन्द्र शर्मा, पौदल्ल्यूडी के अधीक्षण अभियन्ता भूरी सिंह, जयपुर डिस्कॉर्म के अधीक्षण अभियन्ता सुधीर पाण्डे, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियन्ता रमेश चन्द शर्मा, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक पी.सी. मीणा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक लक्ष्मण सिंह, महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक महेश चंद गुप्ता, रीको के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक परेश सक्सेना, पश्चिमालन विभाग के संयुक्त निदेशक रमेश मीणा, एलडीएम बाबूलाल पालरिया, पर्यटन विभाग की उप निदेशक टीना यादव, राजीविका की डीपीएम रेखारानी व्यास सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

**आखिल भारतीय जायसवाल सवेवगाय माहला महासभा का शपथग्रहण समारोह,
युवक-युवती परिचय सम्मेलन एवं वृद्धजन सम्मान समारोह हुआ संपन्न**

जयपुर टाइम्स



जयपुर(कास.)। जयपुर स्थित अग्रवाल कालेज ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महिला महासभा का शपथग्रहण कार्यक्रम एवं सर्ववर्गीय जायसवाल समाज, जयपुर द्वारा आयोजित युवक-युवती परिचय सम्मेलन एवं वृद्धजन सम्मान समारोह का भव्य आयोजन हुआ। सर्वप्रथम ध्वजारोहण एवं भगवान् सहस्रबाहु अर्जुन की आदमकद फ़ोटो पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ञलित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि किशोर हेमराज जायसवाल, मदनलाल प्रभातीलाल जायसवाल, शिवचरण हाडा, कर्हृयालाल पारेता, हरीश कलात रहे एवं अति विशिष्ट अतिथि संजय जायसवाल, राजेंद्र जायसवाल, आदित्य वर्धनम, उत्तमचंद चौधरी, गौरव जायसवाल, आनंद सिंह मेवाड़ा, जुगल किशोर जायसवाल रहे। अभी हाल ही में घोषित अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के मुख्य महासभा की नव निर्वाचित कार्यकारिणी, पदाधिकारियों एवं महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष पूनम गुप्ता, महासचिव हर्षा जायसवाल, कोषाध्यक्ष मनीषा सुवालका एवं पूरी टीम को राष्ट्रीय अध्यक्ष मदनलाल जायसवाल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ

लोहिया पाड़ी व्यापार समिति द्वारा किया स्वागत



वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तिकरण हेतु जिला स्तरीय कार्यशाला का सफल आयोजन

मारत विकास पारषद् अलवर एव भा. वि.प अलवर चैरिटेबल ट्रस्ट ने लगाया शिविर



**गृहम का लोन
महिला एवं बाल
संस्कार शिविर में
बच्चे ले रहे हैं रुचि**

जयपुर टाइम

अलवर(निस.)। भारत विकास परिषद् अलवर एवं भा. वि.प अलवर चैरिटेबल द्रस्ट द्वारा ग्रीष्मकालीन महिला एवं बाल संस्कार शिविर का आयोजन औसवाल स्कूल अलवर में आयोजित किया जा रहा है। प्रकल्प संयोजक महिला शिविर आशा भित्ति ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में नृत्य, योगा, जूडो-कराटे, डोलक, ड्राइंग पैटेंग, मैंहंदी, सिलाई, आर्ट अंडर क्राफ्ट, कैलेग्राफी, व्यूटीशियन सहित अन्य अभिरुचियों का प्रशिक्षण अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा दिलवाया जा रहा है। बाल संस्कार कार्यक्रम प्रकल्प संयोजक महिला अनुराधा चौहान ने सूचित किया कि बाल संस्कार शिविर में भाग ले रहे बच्चों को अभिरुचि के अनुसार तो प्रशिक्षण दिया ही जा रहा है पर साथ ही उन्हें संस्कारित करने के लिए व्या यान सहित अन्य में भी बताया कि हमें भोजन किस प्रकार करना चाहिए और हमारी अच्छी सेहत के लिए हमें भोजन के किन नियमों का पालन करना चाहिए, डॉ सरोज गुप्ता ने बताया कि हमारी प्राचीन संस्कृति का हमारे जीवन में क्या महत्व है। शिविर में लगभग 85 प्रशिक्षणार्थियों (बालिकाओं) ने भाग लिया। प्रशिक्षण का समापन 30 मई 2025 शुक्रवार को किया जायेगा। शाखा सचिव राधे श्याम ने बताया कि शिविर के संचालन में शाखा पदाधिकारियों सहित शाखा के पुरुष एवं महिला सदस्य रमन सोनी, सुरेश गोयल, राधे श्याम, अशोक गुप्ता, रमेश अग्रवाल आशा भित्ति, अनुराधा चौहान, अनुपमा गोयल, नीना सोनी, सरिता राजी, नीना गुप्ता, हेमन्त अग्रवाल, सरोज गुप्ता, कुमुद गुप्ता आदि का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है।

**महिलाओं
यनाना हैं**

A group of men are gathered in an indoor setting with a red and gold patterned carpet. In the center, a man in a yellow shirt and blue jeans holds a white bouquet tied with a ribbon. To his right, an older man in a white kurta and black pants stands with his hands clasped. In the background, other men are standing near tables covered with pink cloths. A large speaker system is visible against the wall.

जे उत्तर दाखिला राखिए पर जो जूता बनाने और डिजिटल ज्ञान के विस्तार पर बल दिया। जिला पैशेनर्स समाज के अध्यक्ष पोहप सिंह यादव ने वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को साझा करते हुए समाधान हेतु सुझाव दिए। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ई-मित्र कियोरस्क की दो विशेष व्यवस्थाएं की गईं, जिनके माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को त्वरित सेवाएं और सहायता उत्तरव्य कराई गई। समापन सत्र में समाज कल्याण विभाग के जिलाधिकारी ने प्रतिभागियों से

'द्रस्ट का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है'

जयपुर टाइम्स



संचालित किया जा रहा है जिसमें डिजिटल सुविधाओं से युक्त पुस्तकें मौजूद हैं जो बच्चों को तकनीकी रूप से सशक्त बना रही हैं। उन्होंने बताया कि वी-शिक्षित ट्रस्ट द्वारा अलवर के विभिन्न क्षेत्रों में लघु मेलों का आयोजन किया गया था जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रशिक्षण, निशुल्क स्वास्थ्य जांच और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इन मेलों में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। उन्होंने अलवर सांसद खेल उत्सव की जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष आयोजित हुए कार्यक्रम में लगभग 13 हजार बच्चों ने हिस्सा

बताया कि वी-शक्ति द्रस्ट महिलाओं को विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और बालिकाओं को चिकित्सकों द्वारा माहवारी के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि इस प्राकृतिक प्रक्रिया के दौरान महिलाओं को न तो घबराना चाहिए और न ही शर्म महसूस करनी चाहिए। इस दौरान राजीविका की डीपीएम रेखारानी व्यास सहित बड़ी संख्या में महिलाएं एवं बालिकाएं मौजूद रही।

जेल सुधार का इंतजार

यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि इन सब मामलों का निपटारा जल्द से जल्द हो। लेकिन कोलेजियम की सिफारिशों के बाद भी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में पद खाली रहते हैं, तो इसके लिए कोई और नहीं, सरकार ही जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर तो जजों की कम संख्या को लेकर कई बार न्यायपालिका की तस्वीर भारत सरकार के सामने में रख चुके हैं। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों व जिला अदालतों में जजों की कमी बरकरार है। विचाराधीन कैदियों की बढ़ती गई तादाद का जजों की संख्या कम होने से सीधा संबंध है। जजों के कम होने से लंबित मामलों की तादाद बढ़ती जाती है, और फलस्वरूप जेलों में विचाराधीन कैदियों की भीड़ भी। इसलिए न्यायिक सुधार के बगैर भारतीय जेलों की दशा नहीं सुधर सकती। व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह असल में एक मानवीय मसला है। विचाराधीन कैदियों में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बेगुनाह हों।

भा रत दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां जेलों में कैदी दूंस-दूंस कर रखे गए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा जारी ताजा आंकड़ों ने साबित कर दिया है कि यदि इस गंभीर मसले को निपटाने में केंद्र, राज्य सरकारों और न्यायपालिका ने सचिन्हनी दिखाई तो आने वाले दिनों में भारतीय जेलों में पांच रखने की भी जगह नहीं रहेगी। ब्यूरो के मुताबिक, भारत में कैदियों की संख्या 4,11,992 है, जिनमें विचाराधीन कैदियों की संख्या 2,78,508 है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि जेलों में बंद 67.6 फीसद लोगों के मामले अदालतों में विचाराधीन हैं। दूसरी गैरतलब बात यह है कि भारतीय जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि देखें तो ऐसा स्पष्ट दिखता है कि दलित, आदिवासी और मुसलिम कैदियों का अनुपात कुल जनसंख्या में उनके अनुपात से कहीं ज्यादा है। ब्यूरो ने माना है कि पचपन फीसद विचाराधीन कैदी इन्हीं समुदायों से ताल्लुक रखते हैं। इस तरह जेलों की हालत आम प्रशासनिक सलूक से भिन्न नहीं है। तमाम सरकारी महकमे इन्हीं समुदायों के साथ सबसे ज्यादा बेरुखी से पेश आते हैं। यह अलग बात है कि इनके हितों की रक्षा के लिए कई विशेष प्रावधान किए गए हैं। दूसरी तरफ, रसूख वाले और दबंग कैदियों का हाल यह रहता है कि जेल में बंद होते हुए भी वे ऐशो-आराम की सारी सुविधाएं हासिल कर लेते हैं, कई तो अपनी आपराधिक गतिविधिया भी वहां से संचालित करते रहते हैं। समझा जा सकता है कि यह सब जेल प्रशासन की मिलीभगत और भष्टाचार के बगैर संभव नहीं होता होगा। यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि इन सब मामलों का निपटारा जल्द से जल्द हो। लेकिन कोलेजियम की सिफारिशों के बाद भी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में पद खाली रहते हैं, तो इसके लिए कोई और नहीं, सरकार ही जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर तो जजों की कम संख्या को लेकर कई बार न्यायपालिका की तस्वीर भारत सरकार के सामने में रख चुके हैं। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों व जिला अदालतों में जजों की कमी बरकरार है। विचाराधीन कैदियों की बढ़ती गई तादाद का जजों की संख्या कम होने से सीधा संबंध है। जजों के कम होने से लंबित मामलों की तादाद बढ़ती जाती है, और फलस्वरूप जेलों में विचाराधीन कैदियों की भीड़ भी। इसलिए न्यायिक सुधार के बगैर भारतीय जेलों की दशा नहीं सुधर सकती। व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह असल में एक मानवीय मसला है। विचाराधीन कैदियों में ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने ऊपर लगे अभियोग की सम्भावित सजा से ज्यादा समय जेल में गुजार चुके होते हैं और मामले का निपटारा न होने के कारण जेल में सड़ते रहते हैं। आजादी के बाद जेल सुधार की दिशा में कई समितियां बनाई गईं। इनमें मुख्य रूप से 1983 में मुल्ला समिति, 1986 में कपूर समिति, 1987 में बनी अच्यर समिति थी। लेकिन इन सारी समितियों के



सुझावों को टंडे बस्ते में डाल दिया गया। तंग कोठरी में कैदियों के रहने की व्यवस्था, दवा की कमी, शैक्षणिक सुविधाओं के अभाव से निजात दिलाने के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक तौर पर कई तरह की सेवाएं प्रदान करने की बात इन सिफारिशों में कही गई थी। इसके अतिरिक्त सजा-काल को स्वरोजगार की तैयारी से जोड़ने का सुझाव भी दिया गया था। मगर आज भी जेल सुधार की दिशा में कोई ठोस पहल शुरू न होना दर्शाता है कि हमारी राज्य-व्यवस्था में फिलहाल इसकी इच्छाशक्ति नहीं है।

इसके पहले के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति और भी भयावह दिखती है। वर्ष 2010 से वर्ष 2014 के बीच तीस फीसद विचाराधीन कैदी तीन साल से अधिक समय से जेल में बंद रहे। वर्ष 2014 में हर दस में से दो को बिना दोषी ठहराए दो वर्ष से अधिक समय जेल में बंद रखा गया। जम्मू कश्मीर में 57 फीसद, गोवा में 52 फीसद, गुजरात में 48 फीसद विचाराधीन कैदी पाए गए। सबसे ज्यादा 18345 मामले उत्तर प्रदेश में देखे गए।

विचाराधीन कैदियों को दोष सिद्ध होने तक निर्दोष माना जाता है। यह प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी है। लेकिन सच्चाई यह है कि जेल के अंदर उन्हें हिरासत के दौरान मनोवैज्ञानिक और शारीरिक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। बहुत सारे विचाराधीन कैदियों को काई कानूनी सहायता नहीं मिल पाती। असल में जेल में रहते हुए उनके पास संसाधनों का अभाव रहता है। इतना ही नहीं, बकाल से बात करने का मौका भी नहीं मिलता। ताजा आंकड़ों के मुताबिक जेलों में कैद पचहत्तर फीसद कैदी या तो अनपढ़ हैं या फिर अधिक से अधिक दसवीं कक्षा तक पढ़े हुए हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को गरिमापूर्ण ढंग से जीने के अधिकार का भरोसा दिलाता है। इसी अनुच्छेद का हवाला देते हुए सुप्रीम

कोर्ट ने वर्ष 1980 में विचाराधीन मामलों की त्वारिख सुनवाई के आदेश दिए थे। अधिकांश विचाराधीन कैदी गरीब और वंचित सामाजिक समूहों से आते हैं जो काफ़ी कम पढ़े लिखे होते हैं। इसलिए उनका आवाज दबा दी जाती है। वर्ष 2005 में लागू दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 436-ए में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई कैदी, उसके ऊपर लगाए गए अभियोग की अधिकतम संभावित सजा की आधं अवधि फैसले के इंतजार में जेल में गुजार चुका है तो अदालत उसे निजी मुचलके या बिना किसी जमानत के ही रिहा कर सकती है। ऐसी बात भी नहीं है कि केंद्र सरकार का ध्यान इस ओर नहीं आकृष्ट कराया गया। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरसी लाहोटी ने 1,382 जेलों के अव्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट को वर्ष 2013 में एक पत्र लिखा। उसके बाद जिलों में विचाराधीन कैदी समीक्षा समिति की स्थापना की गई और वर्ष 2015 से 31 जनवरी 2016 के बीच कम से कम छह हजार विचाराधीन कैदियों को रिहा भी किया गया। यहां इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि जितने कैदी रिहा किए गए वे भारतीय जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की कुल संख्या के महज दो फीसद थे। वर्ष 2013 में भी जेलों में हुए सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया था कि जेल रिकार्ड में भारी विसंगतियां हैं। साथ ही, सूचना प्रणाली का प्रबंधन भी सही नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रभावी कानूनी सहायता की कमी महिला पुलिस के अभाव, मार्गरक्षक पुलिस और वीडियो कॉन्फ्रैंस की भारी कमी के चलते भी कैदियों की संख्या में इजाफा होता है। भारत में जेलों की क्षमता से 112 फीसद ज्यादा कैदी वहां टुकसे हुए हैं कुल कैदियों में डक्टरीस फीसद मुसलिम हैं। मुसलिम कैदियों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश की जेलों में है। उसके बाद बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का नंबर आता है।

सम्पादकीय



एक बार फिर प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर वह आतंकवाद का रस्ता नहीं छोड़ेगा, तो उसे और बुरे नीतिये भुगतने पड़ सकते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने जिस सूझबूझ और शौर्य के साथ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, वह एक बड़ी मिसात है। उसके बाद पाकिस्तान के हुक्मरान भी सोचने पर विवश हुए कि आतंकवाद को पोसने का इतना बड़ा खामियाजा देश को उठाना पड़ा है। मगर चूंकि वहां की सेना और खुफिया एजेंसी आतंकवाद को भारत के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती रही हैं, इसलिए वे अब भी अपने रास्ते में बदलाव को तैयार नहीं दिखा रही हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात को जोर देकर रेखांकित किया कि पाकिस्तान का एकमात्र मकसद भारत से नफरत करना और इसे नुकसान पहुंचाने के तरीके सोचना है, जबकि हमारे देश ने गरीबी खत्म करने और आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री के इस बयान पर पाकिस्तान की तिलमिलाहट स्वाभाविक है। तुरंत इसके जवाब में उसने प्रतिक्रिया दी कि भारतीय प्रधानमंत्री के इस बयान से इस क्षेत्र में अशांति का खतरा पैदा हो गया है, जबकि पाकिस्तान अमन चाहता है। हालांकि इस तरह की विरोधाभासी प्रतिक्रियाएं वह सदा से देता आया है। आपरेशन सिंदूर के बाद भाजपा पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। सरकार ने दुनिया के अलग-अलग देशों में पाकिस्तान की हकीकत बताने और अपना पक्ष खखने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने भी गुजरात में दो दिन की रैली की। उसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान को खरी-खरी सुनाई। सरकार ने बार-बार रेखांकित किया है कि आपरेशन सिंदूर फिलहाल स्थगित है, वह समाप्त नहीं हुआ है। यानी वह अब भी सक्रिय है और पाकिस्तान की हरकतों पर नजर बनाए हुए हैं। जाहिर है, इससे पाकिस्तान में घबराहट है। बेशक वह कहता है कि भारत के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है, मगर हकीकत यही है कि जिस दौर से वह गुजर रहा है, फिलहाल वह किसी भी तरह के सैन्य संघर्ष का बोझ वहन कर पाने की स्थिति में नहीं है। अगर वह सचमुच भारत का मुकाबला कर सकते की स्थिति में होता तो, जैसा कि भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है, पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी आपरेशन सिंदूर पर विराम लगाने की गुहार न लगाते। ऐसी स्थितियों में उसके नेता बेशक सार्वजनिक बयानों में भारत पर हमला करते रहे हैं, पर जमीनी हकीकत हमेशा उससे दूर रही है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी स्थितियों से ही काफी परेशान है। उसकी माली हालत खस्ता हो चुकी है। कर्ज और इमदाद के भरोसे उसकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। बल्लूचिस्तान के विद्रोही उसकी नाक में दम किए हुए हैं। इधर भारत ने सिंधु जल समझौता और व्यापारिक गतिविधियां स्थगित करके और परेशानी पैदा कर दी है। ऊपर से भारत पूरी दुनिया में उसकी असलियत बताने में जुटा है। इस तरह पाकिस्तान पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में लगातार अलग-थलग पड़ता रहा है। ऐसे में उसके हुक्मरान को अपनी सेना और खुफिया एजेंसी की भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने के रास्ते तलाशने ही होंगे। प्रधानमंत्री ने फिर से भारत का रुख स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी रूप में आतंकवाद को बर्दाशत नहीं करेगा और इसके लिए पाकिस्तान को सबक सिखा कर रहेगा।

बदलाव की परतें



ए के ओर जहां वे सक्षम हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं और अपने परिवार और देश का नाम रोशन कर रही हैं, वहाँ एक ऐसा तबका भी है, जहां औरतों को स्वतंत्रता के नाम पर केवल स्कूल तक ही जाने की अनुमति है। एक ओर उन्हीं स्कूलों में महिला शिक्षिका है और दूसरी ओर वहाँ कुछ ऐसी भी बच्चियां हैं, जिन्हें सिर्फ एक निश्चित कक्षा तक पढ़ने की स्वतंत्रता मिली है। महिलाएं देश के लिए स्वर्ण पदक जीत रही हैं तो साथ ही देश के किसी कोने में ऐसी भी महिलाएं हैं, जिन्हें ऐसा सपना देखते तक का भी अधिकार नहीं है।

बच्चियों के लिए आदर्श बताते हैं, वही अपने घर के महिलाओं और अपनी बच्चियों को इतना अधिकार हासिल नहीं करने देते कि वे अपने सपने का फैसला खुद कर सकें और सपने से जुड़े कार्य कर सकें। दरअसल, जब से कुछ महिलाओं ने सारी बंदिशें तोड़ कर खुद को साधित किया है, तब से कथित महान पुरुष ज्ञानियों की चिंता बढ़ने लगी कि कहाँ उनके ज्ञान पर संदेह उत्पन्न न हो। इसलिए नए सामाजिक नियम-कानून, धर्म और सदियों से चली आ रही परंपरा का नाम दे कर और बंदिशें लगाई गईं और कहा गया कि ये महिलाओं के भले के लिए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मातृ देवी या एक्र मातृसत्तात्मक समाज होने के प्रमाण मिलते हैं। इससे यह पता चलता है कि मौजूदा दौर की भेदभाव की भावना सदैव नहीं थी। यह भेदभाव समय के साथ परिवर्तित स्थितियों के कारण हुई और यह भावना लोगों के दिमाग में बैठ गई। आज के जमाने में जहां महिलाएं अपने परिवार के साथ देश का भी नाम रोशन कर रही हैं।

वहीं समाज में बलात्कार, यौन उत्पीड़न और महिला उत्पीड़न के अन्य अपराध बढ़ते जा रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की 2019 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में बलात्कार के 32,033 के मामले या औसतन 88 मामले प्रतिदिन दर्ज किए गए। महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों की तस्वीर भी बेहद अफसोसनाक है। इससे यह पता चलता है कि समाज में चाहे जितना भी बदलाव आ जाए, स्त्रियां खुद में चाहे जितना भी बदलाव कर लें, पुरुष की संकीर्ण मानसिकता का कोई अंत नहीं।

फिर उन्हें मैंने एक कहानी सुनाई। कहानी क्या थी, बस इस पृथ्वी के निर्माण की बातें थीं। चांद था, धरती थी और कुछ संवाद थे। संवाद के साथ बोलने की शैली थी। सवाल फिर भी उठे। सवालों में यह भी शामिल था कि यह कहानी क्यों अच्छी लगी या क्या यह खराब लगी! इसका जवाब प्रतिभागियों ने दिय कि कहानी में जान डाल दी गई थी। भाव-भिंगमा, शब्दों के उतार-चढ़ाव, हाव-भाव सब कुछ थे। लेकिन हम शिक्षक हैं, कलाकार नहीं, इसलिए हमें यह शैली नहीं आती। इस पर मैंने कहा कि माना कि आप कलाकार या अभिनेता नहीं हैं

‘पा कहानी पढ़ना और पढ़ना दो संबन्धित वाक्य है। जो कथाकार है, संभव है वह कहानी शिक्षण की वारीकियों को शिक्षकों तक संप्रेषित न कर पाए। यह भी हो सकता है कि कहानी विधि को पढ़ाने वाला शिक्षण में तो बेहतर हो, लेकिन उसने कहानियां न लिखी हों। यह भी संयोग हो सकता है कि जो कहानी लिखते भी बेहतरीन हों और कक्षा में शिक्षकों को कहानी पढ़ाने के कौशल में भी प्रवीण हों। कक्षा में जब तीस-चालीस शिक्षक हों तो ‘बाल कहानियाँ’ कैसे पढ़ाई जाएं विषय पर सिद्धांत रूप में और कहानी के तत्त्वों पर प्रेरे दिन बातें की जा सकती हैं। लेकिन एक चुनौती यह है कि इसे सुन कर प्रतिभागी सोने न लगें। ऐसा ही एक तजुर्बा पिछले दिनों हुआ। प्राथमिक कक्षा के लगभग तीस शिक्षक कक्ष में उपरिट थे। भाषा, भाषा शिक्षण आदि पर



कलाकार या अभिनेता नहीं हैं, लेकिन अभ्यास करने से इस कौशल को सीख सकते हैं। कुछ लोग सहमत हुए तो कुछ ने सहमति में सिर हिला दिया। लैकिन सच यही है कि कलाकार भी अभ्यास के माध्यम से अपनी कला और दक्षता को मांजता है। अगर शिक्षक कहानी कहने की कला को सीखना और मांजना चाहता है तो अभ्यास वह रास्ता है, जिसके जरिए वह कहानी कहन और कहानी शिक्षण में प्रवेश कर सकता है। सवाल है कि कहानी से आपेक्षा क्या है? बच्चों को कहानी क्यों सुनाई जाए? कहानी सुनाने और कहानी लिखने के प्रति बच्चों को कैसे प्रेरित करें? इस पर हम संवाद के जरिए आगे बढ़ते रहे। प्राथमिक कक्षाओं में शामिल विभिन्न कहानियों के हवाले से यह समझने की कोशिश की जा रही थी कि एक बाल कहानी में किन मुख्य तत्त्वों को शामिल किया जाना चाहिए। कहानी है तो उसमें कोई पात्र होगा। जैसे इंदगाह में दादी, हामिद, बाजार में दुकानदार हैं आदि। जब पात्र होंगे तो वे कुछ बोलेंगे भी। कहन है तो हर पात्र अपनी प्रकृति के अनुरूप ही बोलेगा, वैसे ही बर्ताव करेगा। इसलिए कहानी में संवाद होना जरूरी है। संवाद को कहने की शैली भी महत्वपूर्ण है किस अंदाज में कहना है, यह कहन वाले पर निर्भर करता है कि कहानी के पात्र के साथ ज्ञाय कर पा रहा है या नहीं। कहानी के पात्र आकाश से नहीं आएंगे, बल्कि इसी समाज और परिवेश से आएंगे। ठीक वैसे ही जैसे हमारे आसपास भिन्न तरह के परिवेशीय पात्र होते हैं हर पात्र अपने साथ परिवेश लाता है। कहानी कब की है, कहानी की है, कौन-कौन इसकी कहानी में शामिल है। कहानी के पात्रों के परिवेश के मूलाधिक संवाद और संवाद की अदायगी की शैली बदल जाती है। कहानी में पात्र आ गए। पात्रों के साथ संवाद भी आया संवाद के साथ परिवेश भी कहानी में आ गई। परिवेश के अनुसार भाषा और शब्दों का चुनाव भी आ चुका। अब कहानी को कहने के लिए जिन कौशलों की आवश्यकता पड़ती है, वह है कहने की शैली। इसलिए हमने कहानी की शैलियां बताने के बजाय प्रतिभागियों में कहानी के खंडों को बांट दिया, जिसमें संवाद भी थे। उन कहानियों को पढ़ना और बोलना था। कैसे भाव के साथ बोलें और पढ़ें, इसकी समझ मजबूत करनी थी। इसलिए कहानी का बाचन और पठन कराया गया।



‘हेरा फेरी ३’
कॉन्ट्रोवर्सी पर
बोले डायरेक्टर
प्रियदर्शन

परेश रावल के फिल्म 'हेरा फेरी 3' छोड़ने की खबर ने फैस और फिल्म इंडस्ट्री को चौंका दिया है। फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन ने अब इस पूरे मासले पर चुप्पी तोड़ते हुए अमर उजाला से एकसवलूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि परेश ने यह फैसला करने से पहले उन्हें कोई जानकारी नहीं दी थी। वो खुद इस स्थिति से हैरान और निराश हैं।

आज तक परेश ने इस बारे में बात नहीं की

बातचीत में प्रियदर्शन ने कहा, फिल्म शुरू होने से पहले मैंने तीनों झु अक्षय, सुनील और परेश झु से विलयर पूछा था कि वया आप लोग तैयार हैं? सबने कहा झु हा। पिछमने एक दिन शूट भी किया। सब स्मृद चला। लेकिन अचानक परेश जी के हटने की खबर आई... बिना कुछ बोले, बिना को कारण बताए। आज तक उन्होंने मुझसे इस बारे में कोई बात ही नहीं की।'

‘भूत बंगला’ के सेट पर
कोई तनाव नहीं दिखा

डायरेक्टर ने आगे बताया, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। हाल ही में हमने 'भूत बंगला' की शूटिंग पूरी की। इस फ़िल्म में भी अक्षय और परेश दोनों साथ थे। वहाँ मैं सब कुछ नॉर्मल था। दोनों के बीच बिल्डूल कॉडियल और प्रॉफेशनल रिश्ता था। कोई

तनाव नजर नहीं आया।
वहीं जब हमने प्रियदर्शन से पूछा कि वया
वाकई अक्षय कुमार ने परेश रावल पर 25
करोड़ का दावा ठोका है, तो उन्होंने कहा,
इस फिल्म के राइट्स और प्रोडक्शन अक्षय
कुमार संभाल रहे थे। ऐसे में अगर किसी
को नुकसान हुआ है तो वो सिर्फ अक्षय है।
अगर परेश जी को काई दिक्षित थी तो कम
से कम बात करते। खैर, मैं सिर्फ
डायरेक्टर हूँ। मुझे नहीं पता उनके और
अक्षय के बीच वया हुआ? ना उन्होंने कछ
बताया, ना ही कोई बातचीत की। मैं पूरी
तरह ब्लैक हूँ।'



करिश्मा तन्हा को नहीं
मिल रहा ढंग का काम



**प्रभास की फिल्म छोड़
दीपिका ने थामा अल्लू
अर्जुन का दामन**

हीरोइन नंबर वन दीपिका पादुकोण की निर्देशक संदीप रेही वांगा से खटक गई है। वह अब उनकी फिल्म 'स्प्रिटर' में शायद ही काम करें वयोंकि दीपिका के अब एक दिन में सिर्फ आठ घंटे ही काम करने के नए नियम से संदीप खुश नहीं थे। 'स्प्रिटर' की डेट्स दीपिका ने फिल्म 'जवान' के अपने निर्देशक एटली की झोली में डाल दी हैं, जो जल्द ही अभिनेता अल्लू अर्जुन के साथ एक मेंगा बजट फिल्म करने जा रही हैं।

फिल्म 'एनिमल' के बाद इसके निर्देशक संदीप रेही वांगा अब तक दूसरी फिल्म शुरू नहीं कर पाए हैं। लोगों को इसकी सीक्ल एनिमल पार्क' का बेसब्री से इंतजार है लेकिन उससे पहले संदीप का वादा प्रभास के साथ फिल्म 'स्प्रिटर' पूरी करने का है। इस फिल्म की शूटिंग बीते साल ही शुरू हो जानी थी, लेकिन दीपिका के मां बनने की खबरें आने के बाद संदीप ने इस फिल्म की शूटिंग आगे के लिए ठाल दी। अब दीपिका के मां बनने के बाद जो पहली फिल्म शुरू होनी थी, उसमें सबसे पहले 'स्प्रिटर' का ही नंबर था। फिल्म के निर्माता इस फिल्म के लिए दीपिका को 20 करोड़ रुपये देने की बात भी मांग गए थे, लेकिन धूँक संदीप रेही वांगा का काम करने का स्टाइल अलग है तो दीपिका पहले से ही कुछ बातें लिखित में चाह रही थी। जानकारी के मुताबिक दीपिका ने एक दिन में सिर्फ आठ घंटे ही काम करने की शर्त रखी और ये भी कि वह तेलगु में अपनी डालिंग नहीं करेगी।



'स्पेशल ऑप्स 2' ही नहीं कई और सीरीज में दिखीं स्पाई स्टोरीज

हाल ही में केके मेनन स्टारर वेब सीरीज 'स्पेशल ऑप्स 2' का टीजर एलीज हुआ, जल्द ही यह वेब सीरीज दर्शकों को देखने को मिलेगी। इस स्पाई सीरीज के पहले सीजन को दर्शकों ने काफी सराहा था। इस सीरीज के अलावा भी स्पाई यानी जासूसों पर आधारित

सीरीज बनी हैं। जानिए, ऐसी ही कुछ चर्चित सीरीज के बारे में।

क्राइम के अलावा जासूसी कहानियों पर बेस्ट सीरीज भी दर्शकों को काफी पसंद आती हैं। कई सीरीज की पॉपुलरिटी इतनी बढ़ जाती है कि इसके कई सीजन आते हैं। जल्द ही 'रेपेशल ऑफ्स' के दूसरे सीजन



द नाइट मैनेजर
साल 2023 में 'द
नाइट मैनेजर' नाम
की एक वेब सीरीज
रिलीज हुई। इसमें
अनिल कपूर ने
नेटोवर रोल किया
था और जासूस के
रोल में आदित्य रॉय⁺
कपूर नजर आए

The image shows the front cover of a DVD case for the movie "The Family Man". The cover features a man in a dark suit and tie looking directly at the camera. In the background, there is a blurred scene of what appears to be a burning building or a fire. The title "THE FAMILY MAN" is prominently displayed in large, bold, yellow letters across the bottom of the cover.

सीरीज़ में आदित्य
रॉय कपूर एक पूर्ण
नी सेना के
ऑफिसर बने हैं,
जो एक मिशन के
लिए जासूस बनते हैं। इसके
और विलेन के बुरे झारादों को नाकाम करते हैं।

ध्यान भी रखना है साथ ही उनसे अपनी सीक्रेट एजेंट्स

का पहचान भा छुपाना ह

बार्ड आफ ब्लड

त किया था।

मुख्यविवर

